

पहली बार सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर बंटी जम्मू-कश्मीर कांग्रेस इकाई

इस दरार की जड़ हैं, प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हमीद कर्रा जिन्हें राहुल गांधी की चॉइस बताया जाता है

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 जून। कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई में विभाजन अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है। विवाद का मुख्य कारण जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष अब्दुल हमीद कर्रा हैं, जो कश्मीर से आते हैं।

यह संभवतः पहला अवसर है, जब जम्मू और कश्मीर की इकाइयाँ सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित नजर आ रही हैं। कर्रा के आलोचकों का कहना है कि उनमें न तो कोई राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है और न ही व्यापक और समावेशी दृष्टि। उनका कहना है कि जम्मू में कांग्रेस की स्थिति तेजी से खराब हो रही है।

उनके अनुसार, कांग्रेस ने कभी भी

- कर्रा पीडीपी से कांग्रेस में आए हैं और अमरनाथ आतंकी हमले पर गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिराने में उनकी अहम भूमिका थी, जब पीडीपी ने भाजपा से हाथ मिलाया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी।
- कर्रा कांग्रेस कल्चर से वाकिफ नहीं हैं और उनकी सोच व नज़रिया राष्ट्रवादी न होकर कश्मीर केन्द्रित और अलगाववादी है।
- यही वजह है कि जम्मू के कांग्रेसी उनसे नाराज़ हैं। उनकी मांग है या तो प्रदेश अध्यक्ष जम्मू का हो या जम्मू की अलग कांग्रेस इकाई बनाई जाए।
- देखना यह है कि अब राहुल क्या करते हैं, क्योंकि, राहुल धमाकेदार भाषण तो देते हैं, पर उसे क्रियान्वित करने का उनका सिस्टम बेहद दयनीय है।

सांप्रदायिक राजनीति नहीं की, लेकिन कर्रा के नेतृत्व में पार्टी में सांप्रदायिक

रूझान आ रहे हैं, जिससे जम्मू में भाजपा से मुकाबला करना कठिन हो गया है। इसका स्पष्ट उदाहरण हाल में हुए जम्मू-कश्मीर के चुनाव हैं, जहाँ कांग्रेस, भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकी तथा कांग्रेस की उम्मीदों के बावजूद, उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और सभी लोग स्तब्ध रह गये।

जम्मू कांग्रेस इकाई की मांग है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जम्मू से होना चाहिए। उनकी मांग है कि यदि ऐसा संभव न हो, तो मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी की तर्ज पर एक अलग समिति बनाई जाए, जैसा कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ किया गया है। उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि कर्रा की सोच पूरी तरह कश्मीर-केन्द्रित है और वे केवल कश्मीर पर केन्द्रित सोच (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा, नीट पीजी परीक्षा की तारीख

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 जून। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को नेशनल बोर्ड ऑफ एजामिनेशंस (एन.बी.ई.) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 3 अगस्त को नीट पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है। यह परीक्षा पहले 15 जून को होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षा के

- नैशनल बोर्ड ऑफ एजामिनेशन ने 3 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

प्रस्तावित दो शिफ्ट फॉर्मेट पर चिंता जताने के बाद, इसे स्थगित कर दिया गया था। एन.बी.ई. ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि वह नई प्रस्तावित तिथि पर परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की अनुमति दे। यह कदम अदालत के पिछले शुक्रवार के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जातिगत जनगणना में निहित है परिसीमन का भय

बताया जाता है, केन्द्र सरकार जातिगत जनगणना के डेटा के आधार पर नए सिरे से परिसीमन कराने की तैयारी में है

- दक्षिण भारतीय राज्यों को आशंका है कि नए परिसीमन में कम जनसंख्या की वजह से दक्षिण भारतीय राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व घट सकता है और ज्यादा आबादी वाले यूपी, बिहार की सीटें बढ़ सकती हैं।
- स्टालिन ने कहा कि “हम जनसंख्या नियंत्रण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का खामियाजा क्यों भुगतें।”
- ज्ञातव्य है कि देश में अक्टूबर से जातिगत जनगणना शुरू होने जा रही है, जिसकी अधिसूचना 16 जून को जारी होगी।

सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की तरफ से आई है। उन्होंने मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए, इस प्रक्रिया में जानबूझकर विलम्ब करने का आरोप लगाया है। स्टालिन ने चेतावनी दी है कि इसे

विडम्बना ही कहा जायेगा कि तमिलनाडु जैसे राज्यों, जिन्होंने जनसंख्या-नियंत्रण की नीतियाँ सफलतापूर्वक लागू की हैं, को अब लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व में संभावित कमी करके, दंड दिया जा सकता है। भारत के संघीय स्वरूप में बढ़ रहे

क्षेत्रीय असंतुलन की ओर संकेत करते हुये, स्टालिन ने प्रश्न किया है, “सामाजिक नियोजन के मामले में हमारी सफलता की ऐसी कीमत आखिर हम क्यों चुकायें, जबकि दूसरे राज्यों की अनियंत्रित जनसंख्या-वृद्धि के कारण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 13 जून को

कोर्ट ने ईडी जाँच अधिकारी से पूछा कि गवाहों के बयान की वीडियोग्राफी क्यों नहीं की?

जयपुर, 5 जून। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन में घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान, जांच अधिकारी से प्रकरण के अनुसंधान को लेकर कुछ सवाल किए। इसका जवाब देने के लिए जांच अधिकारी ने अदालत से समय मांगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 13 जून को तय की है।

सुनवाई के दौरान, पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने ईडी के जांच अधिकारी से गवाहों के बयानों की वीडियोग्राफी नहीं करने का कारण पूछा। वहीं, पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण में अन्य लोगों की गिरफ्तारी और गवाहों को लेकर भी जांच अधिकारी से सवाल किए। इस पर जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड देखकर जवाब देने का कहते हुए अदालत से समय मांगा। इसका विरोध

- जाँच अधिकारी ने कोर्ट के सवाल का जवाब देने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 13 जून की तारीख तय दी।

करते हुए जोशी के अधिवक्ता वीआर बाजवा ने कहा कि ईडी अनावश्यक समय लेकर उन्हें अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखना चाहती है। इस पर अदालत ने ईडी को जवाब के लिए 13 जून तक का समय दिया है।

महेश जोशी की ओर से अधिवक्ता बाजवा ने कहा कि मामले में गवाह बनाए गए अभियंता ने बयान दिए हैं कि उन्होंने निजी ठेकेदारों से रिश्तत ली थी, तो फिर उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। दूसरी ओर, मनी लॉण्डरिंग के

मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गवाहों की वीडियोग्राफी के निर्देश होने के बावजूद, ईडी ने वीडियोग्राफी नहीं कराई। दूसरी ओर उसे नोटिस देने के एक साल तक कार्रवाई नहीं करने के बाद अचानक उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व, ईडी की ओर से अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा ने कहा कि मामले से जुड़े सह आरोपियों के बयान में आया है कि जोशी तक रिश्तत राशि पहुंचाई जाती थी। वहीं, आरोपियों की फर्म से जोशी के बेटे की फर्म को भी लाखों रुपए का भुगतान किया गया था। अभियोजन पक्ष के पास जोशी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे में यदि उन्हें जमानत दी गई तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले में मामला दर्ज होने के बाद ईडी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भगदड़ पर सिद्धारमैया का एक्शन

बंगलूरु, 05 जून। बंगलूरु में एम. चित्रास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने पर कर्नाटक सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस

- बंगलूरु में चित्रास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ केस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस कमिश्नर सहित कई पुलिस अधिकारियों को सरपैंड कर दिया है।

मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसीपी, सेन्ट्रल डिवीजन डीसीपी, क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर को तत्काल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

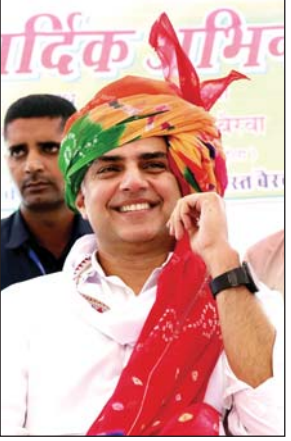
‘राज्य सरकार पंचायतों व निकायों में मनमर्जी से परिसीमन कर रही है’

सचिन पायलट ने टोंक में बैरवा धर्मशाला में नवनिर्गत छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा

टोंक, 5 जून। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने भारत-पाकिस्तान के मध्य युद्धिवराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति बार-बार यह बयान दे रहे हैं कि व्यापार का लालच देकर उन्होंने यह युद्धिवराम कराया है। सरकार द्वारा उनके इस बयान का खण्डन नहीं किया जाना, बयान की पुष्टि करने जैसा है।

कांग्रेस नेता पायलट ने कहा कि पहलगाम में हुई पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद की घटना देश पर आक्रमण था। जब देश की सुरक्षा पर कोई बात आती है तो यह संदेश जाना चाहिए कि देश की सुरक्षा, एकता, अखण्डता के मुद्दे पर सारे 140 करोड़ देशवासि एकजुट हैं और यह संदेश विपक्ष देता है।

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पायलट ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति के युद्ध विराम के बयान का खंडन नहीं करना, बयान की पुष्टि करने जैसा है।



सचिन पायलट

राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाते हुए पायलट ने कहा कि सरकार में कई पावर सेंटर बन चुके हैं। आपस में इतना खिंचाव हो चुका है कि प्रशासन पर उसकी पकड़ खत्म हो चुकी है। यात्रा तीन जुलाई से नौ अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इस साल अमरनाथ की यात्रा 38 दिनों तक चलने वाली है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने कुल

धर्मशाला में 31 लाख रुपये की राशि से नवनिर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों द्वारा भव्य प्रांगण का निर्माण करवाया गया है, परन्तु यह तभी सार्थक होगा, जब समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाये। पायलट आज टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौर पर रहे, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत बमोर, लवादार एवं सोनवा का दौरा कर ग्रामीणों से संवाद किया।

पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पक्के बंदे पर स्थित होटल देवनारायण ढाबा, छावनी सिकिल, बस स्टैंड पर भी भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जिला सोशल मीडिया प्रभारी जरार खान, हंसराज फागणा, फोजुलाम मीणा, सलीम नकवी, महमूद शाह, इरशाद बेग आदि मौजूद थे।

खड़गे-राहुल से मणिपुर के पार्टी नेता मिले

नयी दिल्ली, 05 जून। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को यहां नये कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी के मणिपुर के नेताओं के साथ बैठक कर राज्य में चल रहे हिंसा के तनाव को लेकर ताजा हालात पर चर्चा की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद यह जानकारी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट

में कहा इंदिरा भवन में यहां मणिपुर के नेताओं से मुलाकात कर उनके दर्द, उम्मीदों और दुः संकल्प को सुना। शांति, न्याय और एकता के लिए हमारी लड़ाई जारी है – साथ मिलकर। बैठक में खरो तथा गांधी के अलावा पार्टी हासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतगिरि उलाका, प्रदेश अध्यक्ष केशम मेघचंद्र सिंह सहित कई अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। मणिपुर

में मई 2023 से हिंसा का दौर चल रहा है। राज्य के निवासी दो प्रमुख समुदाय मैती और कुकी के बीच हिंसा हो रही है जिसके कारण 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कांग्रेस का कहना है कि वह शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर का दौरा कर वहां जारी हिंसा रोकने और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का आग्रह कर रही है।

रीवा में ऑटो पर पलटा टूक, सात मरे

रीवा, 05 जून। मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा हुआ। गुरुवार को रीवा जिले में सोहागी पहाड़ के पास एक ऑटो पर सीमेंट की शीट से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। इससे पहले बुधवार को झाबुआ में ट्राला के एक वैन पर पलटने से नौ लोगों की मौत हो गई थी और दो घायल हो गए थे। रीवा में मौत की घाटी कहीं जाने वाली सोहागी घाटी में गुरुवार दोपहर सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 30 पर ऑटो पर सीमेंट की शीटों से लदा ट्रक पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौतें पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय और दो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जल संरक्षण के लिए अधिक श्रमदान का आह्वान किया

उन्होंने रामगढ़ में श्रमदान कार्यक्रम में कहा कि इसमें सभी की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है

जयपुर, 5 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जल ही जीवन है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। आज से शुरू हो रहे “वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान” के तहत, प्रदेशभर में जल संचयन एवं पर्यावरण संरक्षण के तहत विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से आ न किया कि जन सहभागिता को बढ़ावा देते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान में ज्यादा से ज्यादा श्रमदान करें। परंपरागत जलस्रोतों को स्वच्छ बनाएं, जिससे

- मुख्यमंत्री ने रामगढ़ में श्रमदान से पहले जलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर लोकगीत गाते हुए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

वर्षा जल का संचयन हो। मुख्यमंत्री गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के अवसर पर जयपुर के रामगढ़ बांध पर श्रमदान कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सब रामगढ़ बांध को एक बार फिर

किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृहद स्तर पर जनमानस को जोड़ते हुए जल संग्रहण कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान’ शुरू किया गया है। यह अभियान प्रदेशवासियों का अपना अभियान है एवं इसमें सभी की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज गंगा दशमी के दिन अपने आसपास के जल स्रोतों, नदियों, जल धाराओं और तालाबों की पूजा-अर्चना करें तथा इनके संरक्षण में बढ़-चढ़ कर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राज ठाकरे से हाथ मिलाएंगे उद्धव ठाकरे

मुंबई, 5 जून। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (ममसे) के युवा नेता अमित ठाकरे ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वे अपनी पार्टी और शिवसेना (ठाकरे) समूह के बीच गठबंधन के लिए तैयार हैं।

आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अलग हुए चचेरे भाइयों के एक साथ आने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने

- महाराष्ट्र में चर्चा है कि जल्दी ही शिवसेना (ठाकरे) राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से गठबंधन कर सकती है।

जवाब दिया कि उन्हें दोनों नेताओं के एक साथ आने पर कोई आपत्ति नहीं है। अमित ठाकरे ने कहा ‘उन्हें (दोनों नेताओं को) एक-दूसरे से बात करनी चाहिए और इसके बारे में फैसला करना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास एक-दूसरे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत में बनेगी राफेल विमान की बॉडी

नयी दिल्ली, 05 जून। भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ चार उत्पादन हस्तांतरण करार किये हैं जिनके तहत राफेल लड़ाकू विमान की मेन बॉडी का निर्माण भारत में किया जायेगा। इसे फ्यूजलाज कहा जाता है।

इन दोनों कंपनियों ने यहां जारी

- टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से इस सम्बंध में करार किया है।

संयुक्त बयान में कहा कि यह करार देश को एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साझेदारी के दायरे में, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स हैदराबाद में राफेल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)